

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26/2021

अपीलांट-	बनाम	रेस्पोंडेंट्स -
गंगाराम पुत्र धूडाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर		1. नारणाराम पुत्र धूडाराम निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर 2. चैनाराम पुत्र धूडाराम 3. थानाराम पुत्र धूडाराम 4. पुरखाराम पुत्र धूडाराम 5. रामाराम पुत्र सिदाराम 6. तीजों पत्नी सिदाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा कुड़ला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश दिनांक 19.06.2018 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के
विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।


उपस्थिति :-

1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता रेस्पों सं. 1 व 4से6 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पदमाराम परिहार, अधिवक्ता रेस्पों सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोंडेंट सं. 7 व 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।



निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध पेन  गई हैं।

low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79-10, 00-04, 33-08, 45-18 बीघा भूमि के खातेदारान नारणाराम, चैनाराम, थानाराम, पुरखाराम, गंगाराम पि० धूड़ा, रामाराम वल्द सिदाराम, तीजों देवी पत्नी सिदाराम कौम जाट सा० देह ने दिनांक 19.06.2018 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा बेरीवाला गांव के खाता संख्या 51, 67 खसरा न. 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79-10, 00-04, 33-08, 45-18 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 366 में से 79-10 बीघा भूमि दिनांक 22.09.1969 को नारणा, चैना व धूड़ा पुत्र फूसा ने मोल प्रतिफल अदा कर खरीद की थी जिसमें नारणा, चैना एवं धूड़ा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। इसके पश्चात दिनांक 03.05.1975 को अपीलांट व उसके भाईयों रेस्पों० थाना, पुरखा व रेस्पों० सं. 5 व 6 के पिता-पति सिदाराम ने संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 366 में से 45-18 बीघा, खसरा नम्बर 504 रकबा



12/11/21
जिला कलक्टर
बाड़मेर

33-08 बीघा, खसरा नम्बर 503 रकबा 00-04 बीघा गैर मुमकीन ढाणी कुल 79-10 बीघा मोल प्रतिफल अदा कर खरीदी थी। इस खरीद की गई भूमि पर केवल चारों भाईयों का कब्जा काशत था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में अपीलांट को रेस्पोंडेंट ने विश्वास में लेकर व गुमराह कर खेतों का विभाजन कब्जे-काशत एवं रजिस्ट्री अनुसार करवाने हेतु कहकर पटवारी हल्का के पास ले गये तथा चालाकी से खाली कागजों पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा दिये। अपीलांट ने अपने पड़े भाईयों पर विश्वास कर हस्ताक्षर अंकित किये थे किन्तु रेस्पोंडेंट्स ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट के साथ धोखा कर नुकसान पहुंचाने के आशय से सहमति विभाजन करवा दिया। अपीलांट को उसके द्वारा क्रय की गई एवं पिता से बंट में आई भूमि से कम भूमि दी गई एवं अपीलांट की वर्षों पुरानी कीमती व उपजाऊ भूमि से वंचित कर मुख्य सड़क वाली कीमती भूमि रेस्पोंडेंट्स ने हड़ ली तथा अपीलांट को एकल धोरे वाली भूमि दे दी गई। अपीलांट को रेस्पोंडेंट्स की उक्त चालाकी का ज्ञान नहीं था तथा न ही राजस्व रेकॉर्ड को देखने की आवश्यकता हुई। अर्सा 20 दिन पूर्व अपीलांट वक्त खरीद से काबिज होकर काशत कर रहे खेत खसरा नम्बर 651/366, 503 व 504 जिसमें अपीलांट की ढाणियां, टांके व चारबाड़े बने हुए हैं में बारीश का मौसम देखकर सूड़ करने लगा तो रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट्स को सूड़ करने से रोका व झगड़ा करने पर आमादा हुए। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय दिनांक 25.06.2021 को सहमति विभाजन की नकले प्राप्त की तब पता चहा कि राजस्व कर्मचारियों की मिलावट से रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट के साथ धोखाधड़ी द्वारा खरीदशुदा भूमि की जगह अन्य अनुउपजाऊ भूमि अपीलांट को दी गई हैं। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत



अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अलग-अलग पंजिबद्ध दस्तावेजों के द्वारा क्रय की गई भूमि में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश या हकतर्क के खेतों को संयुक्त कर सहमति विभाजन का अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की गई हैं। अपीलांट का वक्त खरीद से खसरा नम्बर 651/366, 503, 504 की भूमि मे 1/4 हिस्से पर रेकॉर्डड कब्जा-काशत व रहवास हैं जिसमें अपीलांट की ढाणी, टांके, बाड़े आदि वर्षों पुराने बने हुए

low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं, अपीलांट वहीं अपनी भूमि विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु रेस्पोंडेंट्स ने अपीलांट के हिस्से की भूमि सड़क निकलने से हुई कीमती भूमि हड़पने के आशय से धोखाधड़ी कर विधि विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 को खसरा नम्बर 651/366, 503, 504, 652/366 की सीमा तक सहमति विभाजन रास्ते की समर्पण भूमि को छोड़ते हुए निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

6. रेस्पोंडेंट्स सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील की ताईद की गई तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को निरस्त कर पुनः नये सिरे विभाजन कराये जाने का निवेदन किया।
7. रेस्पोंडेंट्स सं. 1 व 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर हैं तथा मेरीट पर निर्णय से पूर्व मयाद के बिन्दु पर विचार किया जावे। इसके साथ ही यह भी प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहमति से हुए विभाजन के संबंध में अपील करने का कोई प्रावधान अंकित नहीं है ऐसी दशा में उक्त अपील विचारण योग्य नहीं है। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 1 से 6 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त एवं हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु विभाजन इकरारनामा मय विभाजन नक्शा तैयार करवाकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्णतया विधिनुसार इकरारनामा स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा निराधार एवं कपोल कल्पित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी फरवरी 2020 में होना अंकित किया है तथा विलम्ब का कारण कोविड महामारी होना बताया है जबकि कोविड महामारी का प्रभाव मार्च 2020 से प्रारम्भ हुआ था, इसके अलावा भी अपीलाधीन आदेश वर्ष 2018 में पारित हुआ है जो कोविड महामारी से 2 वर्ष पूर्व का है। अपीलांट ने उक्त दो वर्ष की विलम्ब अवधि का कोई समुचित कारण प्रकट नहीं किया है जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया है। मयाद अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सद्भाविक विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदन पत्र में विलम्ब के समुचित कारणों को दर्शित किया जाना आवश्यक



हैं किन्तु हस्तगत अपील में करीबन 3 वर्ष के असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण का उल्लेख प्रार्थना-पत्र में नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

8. हमने अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79-10, 00-04, 33-08, 45-18 बीघा भूमि के खातेदारान नारणाराम, चेनाराम, थानाराम, पुरखाराम, गंगाराम पि0 धूड़ा, रामाराम वल्द सिदाराम, तीजों देवी पत्नी सिदाराम कौम जाट सा0 देह ने दिनांक 19.06.2018 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा बेरीवाला गांव के खाता संख्या 51, 67 खसरा न. 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79-10, 00-04, 33-08, 45-18 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने-अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 3 वर्ष बाद राजस्व रेकॉर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। यद्यपि रेस्पोंडेंट्स सं. 2 व 3 द्वारा हस्तगत अपील में अपीलांट के कथनों की ताईद की हैं किन्तु रेस्पोंडेंट सं. 1 व 4से6 ने इसका विरोध करते हुए अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के आधार पर यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वयं अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये आवेदन किया गया है। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट्स को बंटवाड़े व रास्ते की समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता



kon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं। अतः अपीलांट्स का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नहीं थे, उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध लगभग 3 साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा मयाद के संबंध में न्यायिक निर्णय नजीर आरबीजे 2000 पेज 706, 2021(2) डीएनजे पेज 804, 2021(1) आरआरटी पेज 130 व अन्य प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बिना विलम्ब माफ करने के प्रार्थना-पत्र निस्तारण किये अपील पर सुनवाई एवं निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया है कि मयाद को निर्णित करने के समय प्रकरण के गुण-अवगुण को मध्यनजर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा निर्णय नजीर एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 1237 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विलम्ब का युक्तियुक्त कारण के अभाव में अपील मयाद बाधित होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित है तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।



निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

kon
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर